DIGITAL ASHAYEIN

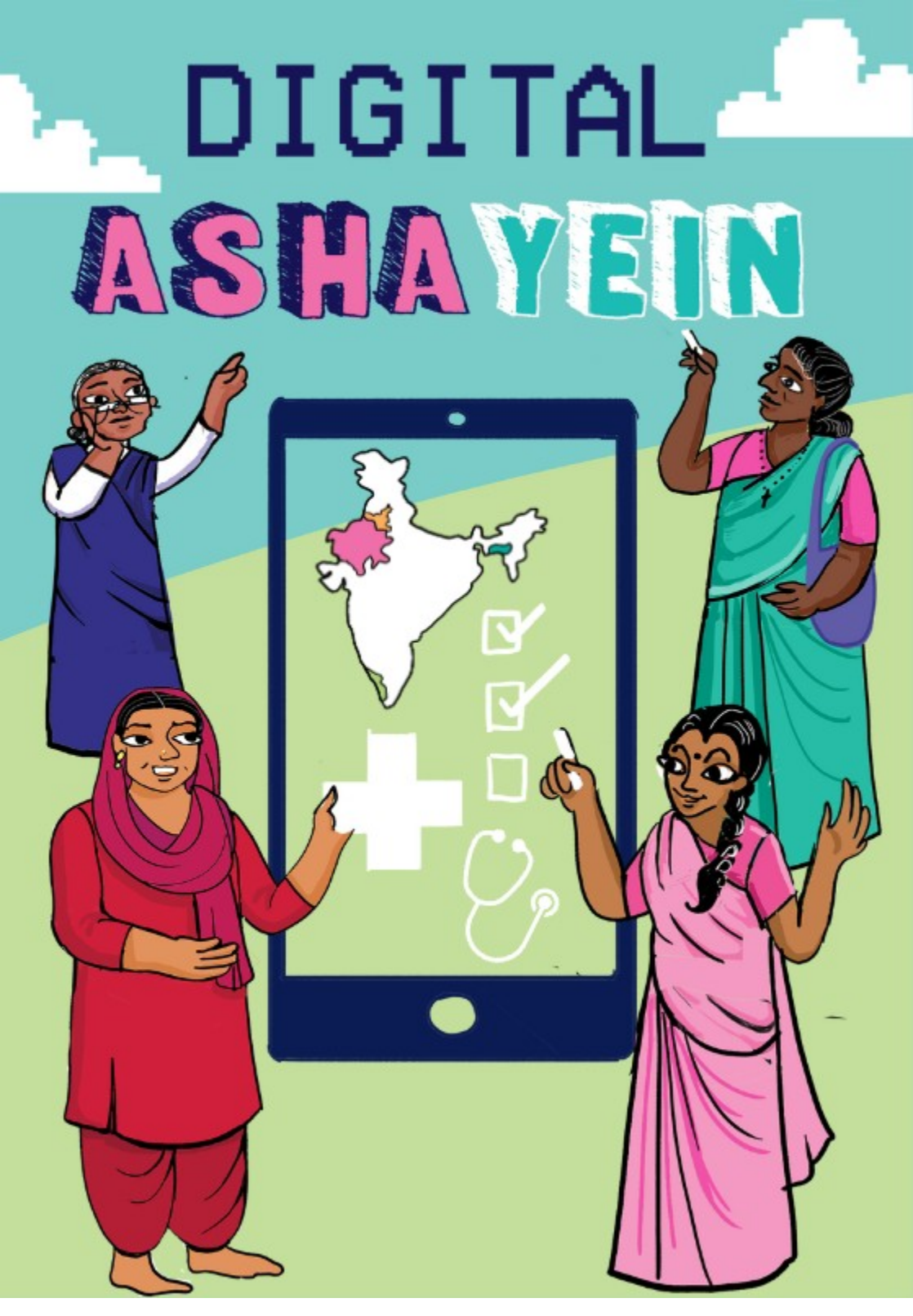

All India ASHA
WORKERS CONVENTION
यह कितनी मज़े की बात है की आज हम बहुत से लोगो से बेहद आसानी से जुड़ जाते हैं।

कमला
(राजस्थान)

मैं एक ग्रुप बनाउंगी और आज की हमारी सभी फोटोज़ तुरंत ही **व्हाट्सएप** पर शेर कर दूंगी!

व्हाट्सएप एक अच्छा आईडिया है, मैं तो पूरा दिन व्हाट्सएप पर ही रहती हूं!

आजकल के बच्चे सब कुछ तेज़ी से सीख लेते है! मेरी बेटी, जो लगभग तुम्हारी उम्र की है कमला, इसमें मेरी मदद करती है।

मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उससे दो कदम पीछे हूं।

लिएंग
(मेघालय)

मारिया
(केरल)

हां सच में! मुझे डिजिटल ऐप्स इस्तेमाल करने में कठिनाई होती है लेकिन अब में सीख गई हूं।

मैं हरियाणा के एक गाँव से हूं।. **जब मुझे स्मार्टफोन मिला तब मेरे परिवार को मुझ पर बहुत गर्व हुआ।** मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूं।

राजबाला
(हरियाणा)

लेकिन अब मुझे यह भी याद नहीं है की आखिरी बार कब मैंने अपनी बेटियों के साथ समय बिताया था। **मैं घर पर भी फोन से अपना काम करने में व्यस्त रहती हूं।'**

क्या आप जानते हैं कि बेहद कम महिलाओं के पास फोन है। जब मैं एक आशा कार्यकर्ता बनी **कार्यकर्ता बनी तो मेरे परिवार के बुजुर्ग कहते थे कि इंटरनेट और यूट्यूब मुझे बिगाड़ देंगे और इसलिए** जवान औरतों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

मेघालय में **आदमी और औरत** के बीच, अन्य जगह की तुलना में कम भेदभाव हैं। लोग ऐसा मानते है की **औरतों को इसका उपयोग केवल विशिष्ट समय पर ही करना चाहिए।**

हा! मैं एक दलित परिवार से आती हूं। मेरे परिवार की औरतों ने कभी स्मार्टफोन नहीं छुआ था, उन्हें ऐसा करने की छूट नहीं थी।
लेकिन लोगो के सामने इसका इस्तेमाल करने पर मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता था। मैं सिर्फ जरूरी कॉल्स का ही जवाब देती थी।' अब भी जब मैं लोगो के सामने फ़ोन का उपयोग करती हूँ, तो लोग कहते हैं,
'देखो वह पूरा दिन फोन में ही घुसी रहती है।'
क्या? सच में!!
हम सभी अपना काम कर रहे होते हैं, और फिर भी लोग उनके मन में हमारे लिए तुरंत ही कोई धारणा बना लेते हैं।

केवल 10–12% महिलाओं के पास फोन है, क्योंकि लैंगिक मानदंड प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं।

मेघालय में स्मार्टफोन बहुत कम लोगों के पास है। 34.7% महिलाएं और 41.2% पुरुष इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी के उपयोग में आदमी और औरत के बीच भेदभाव, अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं।

2014 से, आशा ने डिजिटल टूल्स अपनाए, जिससे 2021 तक आशा के दलित और पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं के बीच स्मार्टफोन के उपयोग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई।

केरल में, 95% लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं और 62% लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, और इस राज्य में आदमी और औरत के बीच भेदभाव सबसे कम है।

नमस्कार मैडम! मैं सोहम हूं और मैंने डिजिटल कार्यो पर आपकी बातचीत सुनी और सोचा कि मुझे भी इससे जुड़ना चाहिए। **डिजिटल टेक विकसित भारत का भविष्य है।** हम वैश्विक अग्रणी है, **आपको इसे अपनाना चाहिए।**

यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, बेटा। हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। **जैसे मेघालय के गाँवों में कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है।**

कई लोगों के पास हमारे द्वारा सुझाए गए ऐप्स डाउनलोड करने के लिए अच्छा स्मार्टफोन नहीं होता है।

हमारी उम्र के आशाओ को ज़्यादा परेशानी होती है **क्योकि हमें उचित ट्रेनिंग नहीं मिली है,** इसलिए स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी का उपयोग थोड़ा मुश्किल है।

हमारे पास जो फोन हैं उनकी कीमत सिर्फ *5-6* हजार है और हमारे महीने का पगार है *7000* रुपये।

एक और बात है, सोहम। जब तक हमें PCTS ऐप का उपयोग नहीं करते तब तक **हमें अपने फोन को रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं मिलते।** कुछ अन्य राज्यों में आशा के कार्यकर्ताओं को तो इतना भी नहीं मिलता। बाकि के सभी खर्चो के अलावा, **रिचार्ज का खर्चा भी हम अपनी जेब से करते हैं।**

हरियाणा में 2021 में हमें इन नारों के साथ हड़ताल करनी पड़ी,

ऑनलाइन काम बंद करो, नहीं तो तनख्वा का प्रबंध करो

तब हरियाणा सरकार ने हमें मुफ्त स्मार्टफोन और डेटा दिया।

सोहम जी, अगला प्रेज़ेंटेशन आपका है। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी और यह आशा कार्यकर्ताओं के काम में कैसे मदद कर सकती है, इसके बारे में आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक है।

मेरे पास इससे भी अच्छा आईडिया है।

क्यों न आशा कार्यकर्ताओं से उनके डिजिटल और टेक के उपयोग के अनुभवों के बारे में सुनें।

मैं तुम्हें केरल के अनुभव के बारे में बताती हूं।

हमारे राज्य ने **निपाह, केरल बाढ़** और यहां तक कि **कोविड** के दौरान ही डिजिटलीकरण के बारे में सोचा था।

हमने **डिजिटल सर्वे** किया है और **डिजिटल ओपीडी** की निगरानी भी की है। हम टेलीमेडिसिन का उपयोग करके रोगियों के साथ चैट भी करते हैं। अब हम शैली ऐप का उपयोग करते हैं।

शैली ऐप क्या है?

2022 में, केरल सरकार ने एक एंड्रॉइड ऐप 'शैली', राज्य में लोगों के बीच जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का पता लगाने और उसे काबू में लाने के लिए लॉन्च किया था।

- डायबिटीज
- हाई ब्लड प्रेशर
- हार्ट की बीमारी
- फेफड़ों के रोग
- जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ
- कैंसर

अब हम डेटा इकट्ठा करने के लिए शैली ऐप का उपयोग करते हैं

Shaili App

राजस्थान डिजिटलीकरण में आगे रहा, जहाँ राज्य द्वारा *2014* में **आशा सॉफ्ट ऐप** और *2023* में ***PCTS* ऐप** लॉन्च किया गया।

हमने राज्य में माताओं और बच्चों को ट्रैक करने के लिए 2023 में PCTS ऐप का उपयोग शुरू किया गया। यह हमारा दोस्त बन गया है और हमें यह बेहद उपयोगी लगता है।

जैसे इस फीचर को देखें। हम हमारे किए जाने वाले कार्यों को ट्रैक कर सकते हैं और इससे हमें अपने **टीकाकरण कार्यक्रमों** को अच्छे से पूरा करने में मदद मिलती है।

इसमें सारा डाटा हर रोज़ दर्ज किया जाता है। इससे **ब्लॉक** और **जिला स्तर** पर हमारे उच्च अधिकारियों को हर एक औरत और बच्चे के डेटा और हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को देखने में मदद मिलती है।

और व्हाट्सएप एक ऐसा ऍप है जो लोगो के बहुत से काम को आसान बनाता है। अब हम टीकाकरण अभियान पर मैसेजिस भेज सकते हैं।

ASHA Soft
The Online Payment and Monitoring System

ऐसा ही एक और ऐप है - आशा सॉफ्ट - जिसमे हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं और हमें मिलने वाले इंसेंटिव्स की जानकारी दिखाई देती है। इससे यह भी पता चलता है कि हमें तनख्वाह मिल गई है या नहीं।

व्हाट्सएप बेहद उपयोगी है। हम व्हाट्सएप पर शिविर, टीकाकरण आदि के बारे में स्टेटस डालते हैं और इसे देखकर बहुत से लोग आते हैं। व्हाट्सएप के कारण हमें इधर-उधर जाना नहीं पड़ता।

हम अन्य आशा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ और उच्च अधिकारियों के साथ भी बात करने के लिए व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं:

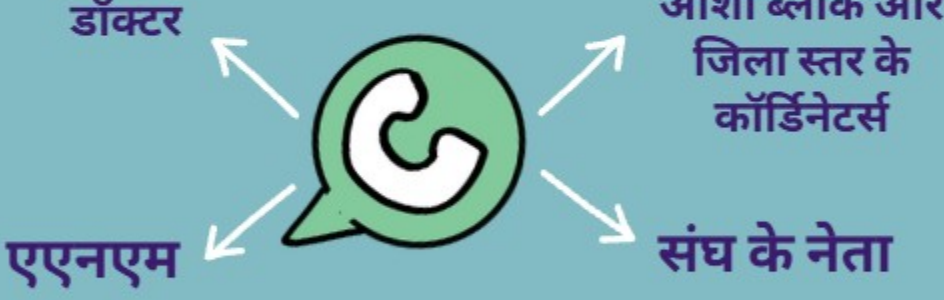

हरियाणा में, ASHAPay ऐप ने हमारी पेमेंट ट्रैकिंग को आसान बना दिया है। तो यह अच्छा है।

लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है।

उदाहरण के लिए, अब हमें **टीबी और एनसीडी** सर्वे जैसे कई **डिजिटल सर्वे**. करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले, हमें सब कुछ कागज पर रिकॉर्ड करना होता है और फिर इसे ऐप पर दर्ज करना होता है।

इससे मेरा काम बढ़ गया है.' ज़्यादातर दिनों में मैं देर रात तक काम करती हूँ,

कभी-कभी सुबह 2 बजे तक।

इन बढ़ते डिजिटल सर्वे से हमारे जैसे आशा के कार्यकर्ताओं के लिए **समाज के साथ मजबूत संबंध** बनाए रखना मुश्किल हो गया हैं।

इससे हम **समाज के लिए किए** जाने वाले आवश्यक कार्यों से दूर होते जा रहे हैं। जो समय मुझे समाज के लोगों के साथ बिताना चाहिए वह अब डिजिटल सर्वे में चला जाता है।

मेरे वार्ड में एक बूढ़ी औरत है, **जिसे हमेशा मुझसे बात करना बेहतर लगता था।** लेकिन इतने ज़्यादा काम के कारण मुझे उनके साथ बैठने का समय ही नहीं मिल पाता।

साथ ही ये डिजिटल सर्वे आशा के कार्यकर्ताओं और समाज के बीच विश्वास की समस्या भी पैदा कर रहे हैं।

डिजिटल कार्यों में ज़्यादा समय लगता है। इससे दूसरे काम, जिनसे पैसे मिल सकते है, घर के काम और परिवार के लिए समय ही नहीं बचता।

हाँ, ज़्यादातर डिजिटल कार्यो के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। सरकार सोचती है कि **'यह औरत मुफ्त में काम करने को तैयार है, उससे जितना संभव हो उतना काम करवाएं'।**

लोग हम पर ध्यान नहीं देते, हमे जानते नहीं और हमारे काम के लिए हमे कम पैसे मिलते हैं।

तो आप यह कह रहे है कि टेक्नोलॉजी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मुश्किलें हैं, है ना?

हम टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण के खिलाफ नहीं हैं।

जैसा कि मैंने कहा, **PCTS** और **आशा सॉफ्ट ऐप** हमारे लिए चीजों को आसान बनाने के लिए तैयार किए गए थे। इनसे पारदर्शिता बढ़ी है।

जब इसका उपयोग केवल डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, तब, हमें परेशानी होती है

या फिर जब हमें केवल डेटा इकट्ठा करने वाले एजेंट के रूप में देखा जाता है, तब यह हमारे लिए एक समस्या है। हम अब चौबीसों घंटे काम करने वाले कर्मचारी बन गए हैं। कोई भी अधिकारी कभी भी हमसे डेटा मांग लेता है।

मेरे लिए, अपना काम कागज़ पर करना बहुत आसान था। हम भुगतान के लिए अक्सर **आशा फर्स्ट ऐप** का उपयोग करने के बजाय **आशा कॉर्डिनेटर्स और एएनएम** पर निर्भर रहते हैं। डिजिटल बदलाव कठिन है लेकिन हमें इसे अपनाना होगा।

जब हम घरों में जाते हैं, तो हमें बच्चों का वजन करते समय या गर्भवती औरतों से बात करते समय तस्वीरें लेनी होती हैं। मुझे फ़ोन का अच्छे से उपयोग करना नहीं आता था, इसलिए मैं सब कुछ कागज़ पर लिखती थी और किसी से इसे भेजने में मेरी मदद करने के लिए कहती थी ।

हम्म, मैं समझता हूँ। यह बदलाव सच में कठिन रहा है। मुझे यकीन है कि सरकार ने हर एक राज्य में सर्वोत्तम संभव ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है?

सोहम, यह सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के बारे में नहीं है। आशा के कार्यकर्ताओं को अक्सर बेहद **कम ट्रेनिंग मिलती है।**

उदाहरण के लिए, हमें PCTS ऐप पर केवल दो दिनों की ट्रेनिंग मिली है और यह आमतौर पर बहुत से लोगों को एक साथ दी जाती है।

हममें से ज़्यादातर लोग एक-दूसरे से या परीक्षण और कोशिश करके या गलती होने पर सीखते हैं, और कभी-कभी अपने बच्चों या परिवार के लोगों से भी।

आशा के युवा कार्यकर्ता आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन हममें से 50 से ऊपर की उम्र वालों के लिए, यह बहुत मुश्किल है।

मुझे लगता है कि ऐप्स के साथ-साथ हमें अन्य डिजिटल टूल्स के बारे में समझाना भी ज़रूरी है।

और उन लोगों का क्या जो हमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए शक की नजर से देखते हैं, उन्हें कौन समझाएं कि यह हमारे काम का एक जरूरी हिस्सा है?

हाँ। *PCTS* के अलावा, आमतौर पर अन्य ऐप्स या डिजिटल सर्वे के लिए भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमें व्हाट्सएप पर सामान्य जानकारी के साथ ऐप्स के लिंक भेजे जाते हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है।

केरल में भी ऐसा ही। हम केरल में डिजिटल टूल्स पर जानकारी और **अक्षय केंद्रों** के माध्यम से डिजिटल टूल्स को सिखने की ट्रेनिंग में सुधार देख रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी मुश्किलें है।

एक ही बार होने वाले ज़ूम मीटिंग ट्रेनिंग सेशन में *100* लोगों में से एक-एक पर ध्यान देना कैसे मुमकिन है?

मेघालय में हममें से ज्यादातर लोग सिर्फ व्हाट्सऐप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को दूसरी ऐप चलानी आती है।

यहां **भाषा की दिक्कत** भी है। मेघालय में लोग **खासी, हिंदी** और **अंग्रेजी** बोलते हैं, लेकिन सारी ट्रेनिंग सिर्फ खासी भाषा में होती है। इसलिए हममें से कई लोगों को समझ नहीं आता कि क्या सिखाया जा रहा है।

उन्होंने बस मोबाइल दिया और कहा, "यहां क्लिक करो...ऐसे करो...बस खत्म। **जब मैं घर पहुंची, तो अटक गई। मुझे पता ही नहीं था कि अब आगे क्या करना है।**

डिजिटल दुनिया की एक और परेशानी वाली बात है।

हमें ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है।

हां! मुझे अश्लील मैसेज मिले हैं।

मेरे साथ काम करने वाले कुछ कार्यकर्त्ता को उन औरतों के पतियों ने **फोन करके लड़ाइयाँ की** हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं। आशा की एक युवा कार्यकर्ता ने इस वजह से अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया था। **हमें उसे रोकना पड़ा।**

मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, राजबाला। आप इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और **आपको इन बाधाओं का सामना अकेले ही करना पड़ रहा है।**

इस बातचीत से मैं बहुत कुछ जान पाया हूँ। मुझे लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऐप डिज़ाइन **करते समय हमें आशा के कार्यकर्ताओं को भी शामिल करना चाहिए।**

अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए ऐप बनाते समय मेरे जैसे टेक्नोलॉजिस्ट को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे?

सोहम, समाज के लिए मुझे काम करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत कम और कभी-कभी बहुत देर से तनख़्वाह मिलती है। फिर भी मैं ये कमा करती हूं क्योंकि यह मेरा जुनून है। टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे समाज, जिसके साथ मैं काम करती हूं, उससे करीब लाएं।

मैं मारिया और कमला के अनुभव से यह देख पा रहा हूं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से तब फायदा हो सकता है जब यह हमें स्वास्थ्य और हमारे भुगतान जैसी चीजों को ट्रैक करने में मदद करें।

टेक्नोलॉजी को हमारे काम का बोझ कम करना चाहिए, न की बढ़ाना।

मेरे हिसाब से डिजिटल टेक्नोलॉजी **कार्यकर्ताओं पर केंद्रित** होनी चाहिए।

कार्यकर्ताओं पर केंद्रित, कैसे?

1. जैसा कि मेरी अन्य बहनों ने कहा, इसे हमारे कार्यों को आसान बनाना चाहिए और उन्हें हमारे और समाज के लिए पारदर्शी बनाना चाहिए।

2. छोटे समूहों के लिए समय पर और उचित डिजिटल ट्रेनिंग, जो व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर हैं।

3. इसमें वृद्ध आशाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए।

4. उन लोगों पर ध्यान दें जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते।

हाँ। और ट्रेनिंग को और अधिक पर्सनलाइज़्ड करने की आवश्यकता है और यह आशा कार्यकर्ता के स्थान के करीब दी जानी ताकि उन्हें कम यात्रा करनी पड़े।

और राज्य में अलग-अलग भाषाओं को ध्यान में रखें।

और आगे में कहना चाहूंगी की हमें इंटरनेट और डेटा के खर्च का भुगतान भी किया जाना चाहिए। हमारे ज्यादातर राज्यों में डेटा रिचार्ज के पैसे पाने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ा है, और अब भी, हम जितना खर्च करते हैं उससे कम मिलता है।

सर, यह वाकई अच्छा होगा अगर स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार हमारे काम की कदर करना शुरू कर दें। हम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें कम महत्व दिया गया है और हमारी सराहना नहीं की गई है।

हमारे साथ किसी सरकारी कर्मचारी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।

सही कहा। हमें जो अधिकार मिले हैं उनमें से कई, वर्षों के विरोध और अपने अधिकारों की मांग के कारण हैं।

हमने कुछ अधिकार हासिल किए हैं लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

2 महीने बाद

आपने हमें दिखाया है कि वास्तविक प्रगति के लिए साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। अब, सुनने और कार्य करने की हमारी बारी है। साथ मिलकर, हम एक लोकतांत्रिक डिजिटल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

आशा कार्य में डिजिटलाइजेशन के एकीकरण की विस्तृत समयरेखा

मेघालय

- **2019** — एनसीडी *[गैर संचारी रोग]*
- **2019** — वॉट्सऐप
- **2022** — आशा फर्स्ट ऐप
- **2023** — यूविन ऐप
- **2023** — आभा कार्ड

- **2023** — आभा ऐप
- **2023** — उविन ऐप
- **2021** — *PMJAY app*
- **2021** — एनसीडी-जीओआई ऐप
- **2021** — ज़ूम और माइक्रोसॉफ्ट टीमें
- **2021** — एमडीएम*360* शील्ड

हरियाणा

- **2014** — एयरटेल सिम कार्ड *(इंटरनेट पैक के बिना)*
- **2017** — दिव्यांग सारथी ऐप से डिजिटल सर्वेक्षण
- **2018** — वोडाफोन सिम कार्ड *(इंटरनेट पैक के बिना)*
- **2019** — वॉट्सऐप
- **2019** — मोबाइल एकेडेमी ऐप
- **2019** — किलकारी ऐप
- **2020** — आशापे ऐप
- **2021** — सिम कार्ड और इंटरनेट वाले स्मार्टफोन

2008 पीसीटीएस पोर्टल *[गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली]*

आशा सॉफ्ट **2015**

2015 वॉट्सऐप

एनसीडी सर्वेक्षण *[गैर संचारी रोग]* **2018–2019**

2020 कोविड आशा सर्वेक्षण ऐप

टीबी सर्वेक्षण **2021**

2021 फेमिली प्लानिंग ऐप

जन कल्याण ऐप **2021**

2021–2022 निरोगी राजस्थान

आयुष्मान भारत **2022–2023**

2023 आशा के लिए पीसीटीएस ऐप

आभा कार्ड **2023–2024**

2018 वॉट्सऐप

2020 *ज़ूम*

2020 ओपीडी में ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं

2021 ईज़ीमैन सॉफ्टवेयर

2021 इंटरनेट के लिए फोन भत्ते को मंजूरी

2021 यूएचआईडी *(कार्ड पर विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान)*

2022 शैली ऐप

2022 ओपीडी *(बाह्य रोगी विभाग)*

एबीएचए *(आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या)* **2023**

NOTES

यह कॉमिक 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं और समाज के लिए उनके आवश्यक स्वास्थ्य सेवा कार्यों के प्रति एक श्रद्धांजलि है।

आईएसएसटी के अध्ययन **"फ्रंटलाइन पर डिजिटलीकरण: हरियाणा, राजस्थान, केरल और मेघालय में आशा के अनुभव"** पर आधारित यह कॉमिक हरियाणा, केरल, राजस्थान और मेघालय की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने देखभाल कार्यों में डिजिटलीकरण लाने के साथ उनके विचार प्रकट करती है। आधारित चित्रण इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे ऊपर से नीचे तक की डिजिटलीकरण की रणनीतियाँ अक्सर पिछड़े हुए वर्ग की महिला कार्यकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर देती हैं।

यह परियोजना एक कार्यकर्ता-केंद्रित, अंतर्संबंधीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है और दर्शाती है कि कैसे समावेशी, सहभागी दृष्टिकोण अधिक लिंग-समान परिणाम ला सकते हैं।

निर्माता

ISST Institute of Social Studies Trust

विकासकर्ता

BEHANBOX

रिसर्च: श्रीरूपा और स्नेहा मक्कड़
अवधारणा: श्रीरूपा, जाह्न्वी अंधारिया, भानुप्रिया, मोनिका शर्मा और दिव्या खन्ना
स्क्रिप्ट: उर्वी सावंत और भानुप्रिया
चित्रण: उर्वी सावंत

आईएसएसटी के बारे में

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट (आईएसएसटी), 1980 में स्थापित, एक गैर-लाभकारी संगठन है जो लिंग, श्रम और आजीविका पर ज्ञान के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हुए, आईएसएसटी कार्य, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिंग आधारित आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है। अनुसंधान, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के माध्यम से लिंग परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, आईएसएसटी चार प्रमुख विषयों पर नीति और अभ्यास की जानकारी देता है: लिंग आधारित हिंसा और कार्य; अनौपचारिकता, जोखिम भरा कार्य और देखभाल; लिंग और कार्य का डिजिटलीकरण; और कार्य की दुनिया को सशक्त बनाने वाली महिलाएँ। ढाई दशकों से अधिक समय से, पूर्वी दिल्ली के कम आय वाले इलाके में स्थित आईएसएसटी के साथी और युवा साथी केंद्रों ने बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किए हैं, उनकी सीखने की यात्रा का समर्थन किया है, और उन्हें लिंग के ख्याल और संवैधानिक मूल्यों से परिचित कराया है।

बेहनबॉक्स के बारे में

बेहनबॉक्स एक पुरस्कार विजेता, महिलाओं द्वारा विकसित एक डिजिटल स्टोरीटेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो भारत में महिलाओं और विभिन्न लिंग के विविध लोगो पर गहन, डेटा संचालित और जमीनी रिपोर्ट तैयार करता है। हम महिलाओं और उनके द्वारा जिए जाने वाले विविध प्रकार के जीवन पर राज्य और समाज के निहितार्थ को समझने के लिए कानून, शासन और नीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा काम, डेटा और साक्ष्य के साथ महिलाओं और गैर-बाइनरी लोगों की जीवित वास्तविकताओं से मेल खाने की लगातार कोशिश करना है। हमारा मिशन परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए लैंगिक मुद्दों को सामान्य बनाना है।